प्रो० सुधीर कुमार सिंह, प्रधानाचार्य, रोहतास महिला कालेज, सासाराम

बी०ए० (आनर्स) खण्ड-III, प्रश्न पत्र-VI ग्रामीण समाजशास्त्र, समाजशास्त्र विभाग

भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास — (A) के बाद क्रमशः

(B) स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास —

भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, नई सरकार ने गाँवों की बिगड़ती दशा को सुधारने का निश्चय किया। 1951 में 82.7% जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी। महात्मा गाँधीजी ने कहा था, दिल्ली भारत नहीं है भारत तो गाँवों में बसता है। अतः यदि हमें भारत को उन्नत करना है तो गाँवों की दशा सुधारनी होगी। उन्होंने नारा दिया था 'गाँवों को वापस चलो'। इस कारण भारत सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए सामुदायिक विकास योजना का शुभारम्भ किया। भारत सरकार के अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, राजनीतिशास्त्रियों एवं बुद्धिजीवियों ने गाँवों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया और अपना अध्ययन कार्य किया। भारत में यहीं से ग्रामीण समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार हुई। भारत सरकार ने ग्रामीण जनता के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की — पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता, भूदान, ग्रामदान एवं सर्वोदय

योजनाओं के द्वारा गांवों का कायाकल्प करने का प्रयास किया गया है। सफलतापूर्वक विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए गांवों की जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक है। ए० आर० देसाई इस संबंध में कहते हैं "ग्रामीण सामाजिक संरचना इसके ढांचे (संरचना) तथा व उद्विकास का व्यवस्थित अध्ययन केवल आवश्यक ही नहीं हो गया बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अनिवार्य हो गया है।" अनेक विद्वानों का अध्ययन सामुदायिक विकास योजनाओं औद्योगीकरण/नगरीकरण के प्रभावों कृषक समाजों, ग्रामीण नेतृत्व, गांवों की बदलती सामाजिक संरचना से संबंधित रहे हैं। एस० सी० दुबे की 'इण्डियन विलेज', डी० एन० मजूमदार की पुस्तक 'रूरल प्रोफाइल' एम० एन० श्रीनिवास की सम्पादित 'इण्डियाज विलेजेज" आदि पुस्तकें ग्रामीण विकास से संबंधित कई प्रकार की ~~सामग्रियाँ~~ जानकारियाँ प्रदान करती हैं।

वर्तमान में पी-एच०डी० डिग्री के लिए, एम०फिल० एवं एम०ए० के डिजरटेशन के लिए अनेक छात्रों ने अपने अध्ययनों द्वारा ग्रामीण समाज पर शोध प्रबंध लिखे हैं अत: आज भारतीय ग्रामीण जीवन का जानकारी देनेवाला प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। वर्तमान दशक में कुछ विश्वविद्यालयों में यह पृथक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात भी है कि भारतीय ग्रामीण समाज पर उपलब्ध साहित्य का संकलन कर उनका समन्वय किया जाए और उचित निष्कर्ष निकाले जाएं तथा ग्रामीण जीवन की समुचित व्याख्या प्रस्तुत की जाए, उनके अतीत और वर्तमान तथा विकास के नियमों को ज्ञात किया जाए। ऐसी स्थिति में गाँवों का उज्जवल भविष्य के निर्माण में ग्रामीण समाजशास्त्र अपनी भागीदारी दे सकेगा।